



DAY 32°
NIGHT 28°
Hi Low

संक्षेप

हाई कोर्ट में जब

आईएएस अफसर को

मांगनी पड़ी माफ़ी, फिर

भी जज ने बैरंग लौटाया

कोच्चि। केरल हाई कोर्ट में एक बेहद

दिलचस्प मामला सामने आया है,

जहां एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी

को अदालत में पेश होकर बिना शर्त

माफ़ी मांगनी पड़ी। केरल के काजू

विकास विभाग के प्रभारी सचिव

आईएएस के बीजू ने कोर्ट की

अवमानना मामले में अपनी गलती तो

मान ली, लेकिन जज साहब उनकी

इस माफ़ी से जरा भी संतुष्ट नजर

नहीं आए। हाई कोर्ट ने उनके

माफ़ीनामे को खारिज करते हुए उन्हें

इसे दोबारा और सुधार के साथ

लिखकर पेश करने का सख्त निर्देश

दिया है। अब इस हाई-प्रोफाइल

मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई

को तय की गई है। जस्टिस ए

बदरुद्दीन कडकमपल्ली मनोज की

ओर से दायर अवमानना याचिका पर

सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आईएएस

अधिकारी के बीजू को खुद अदालत

में पेश होना पड़ा। अपने बचाव में

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बयान पर

गहरा अफसोस है और उनकी भाषा

से ऐसा लग सकता है कि माननीय

कोर्ट के अधिकारों को प्रभावित करने

वाला कोई बयान दिया गया हो। बीजू

ने अपने उस विवादित आदेश की हर

बात को वापस लेने की बात कही और

बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगी।

उन्होंने अदालत में सफाई देते हुए

कहा कि उनकी मंशा कभी भी

न्यायिक समझ पर सवाल उठाने की

नहीं थी, लेकिन भाषा के चयन में

उनसे चूक हो गई है। आईएएस

अधिकारी की दलीलों और माफ़ी के

बावजूद हाई कोर्ट का रुख काफ़ी

सख्त रहा। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में

कहा कि सरकारी अधिकारियों को

पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों

का निर्वहन करना चाहिए और अपनी

किसी भी व्यक्तिगत गलती को छिपाने

के लिए सरकार को ढाल नहीं बनाना

चाहिए।

बारुईपुर लिविंग मामले

में तीन गिरफ्तार, दुष्कर्म

के आरोप में शरूख की

पीट-पीटकर कर दी

गई थी हत्या

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के

बारुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ

दुष्कर्म के बाद भीड़ द्वारा एक शरूख

की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई

थी। अब उस मामले में तीन आरोपियों

को गिरफ्तार किया गया है। अब तक

इस मामले में कुल पांच लोगों की

गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस युवक

को पीट-पीटकर मार डाला गया, वो

निर्दोष था और सीएम शुभेन्द्र

अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है।

सीएम ने युवक के परिवार को

आर्थिक मदद देने का भी एलान किया

है। नाबालिग पीड़िता 4 जुलाई को

दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में

अपने घर से एक दोस्त के लिए

जन्मदिन का तोहफा खरीदने निकली

थी और तभी लापता हो गई थी।

उसके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी

की शिकायत दर्ज कराई थी और एक

दिन बाद उसकी लाश मिली।

लाश मिलने के तुरंत बाद, भीड़ ने

इंद्रजीत मंडल नाम के एक व्यक्ति की

पीट-पीटकर हत्या कर दी, क्योंकि

उन्हें शक था कि वह लड़की के

दुष्कर्म और हत्या में शामिल था। बाद

में, मुख्यमंत्री शुभेन्द्र अधिकारी ने कहा

कि मंडल बेगुनाह था और लिविंग में

शामिल लोगों पर हत्या का आरोप

लगाया जाएगा। अधिकारी शनिवार

को बारुईपुर में दुष्कर्म पीड़िता के

परिवार से मिलने वाले हैं।

आर्यावर्त क्रांति

'दुनिया को नया मॉडल दे रहा है भारत...'ऑकलैंड में बोले पीएम मोदी, बताई 30 साल पुराने मफलर की कहानी



ऑकलैंड। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वैश्विक मंच से भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति का दमदार खाका पेश किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के एक भव्य कार्यक्रम 'क्रिया ओरा मोदी' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम वैश्विक चुनौतियों और

मंदी के दौर के बावजूद भारत के विकास की गति अभूतपूर्व है और आज देश दुनिया को विकास का एक बिल्कुल नया मॉडल दे रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के दौरान मंच पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी का गर्वजोशी से स्वागत किया।

डिजिटल क्रांति और अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान
प्रधानमंत्री ने भारत के नए विकास मॉडल के उदाहरण देते हुए तकनीकी क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल लेनदेन हो रहे हैं, जिसने दुनिया को हैरान किया है। इसके साथ ही भारत अब ड्रोन प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

'दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है भारत'

प्रवासी भारतीयों के भारी उत्साह, तालियों की गड़गड़ाहट और 'मोदी-मोदी' के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा, 'वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत जिस गति से विकास कर रहा है,

वह अभूतपूर्व है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है।'

भारत-न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौता लिखगा नया इतिहास

दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर

40 साल बाद भारतीय पीएम दौरा, 30 साल पुराना मफलर

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा के अंतिम चरण में शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचे थे। पिछले 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंच से एक पुराना मफलर दिखाकर अपनी पुरानी यादें ताजा कीं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जीवन में आने से पहले, करीब 25-30 वर्ष पूर्व जब वे एक साधारण नागरिक के रूप में न्यूजीलैंड आए थे, तब उन्हें यह मफलर उपहार में मिला था, जिसे उन्होंने आज भी संभल कर रखा है।

बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध सुखद स्मृतियों, स्थायी मित्रता, साझा मूल्यों और परस्पर प्रतिबद्धता पर टिके हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच होने वाला आगामी व्यापार समझौता विकसित राष्ट्र बनने की भारत

नवाचारकर्ताओं और हमारे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।' उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्णय किया है, जिसके तहत स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को एक रणैतिहासिक पहल बताया और कहा कि भारत की लगातार तेज आर्थिक वृद्धि, युवा व कुशल कार्यबल, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल ब्रॉन्त, नई पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विस्तार और लगातार जारी आर्थिक सुधार न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए व्यापार और निवेश के क्षेत्र में व्यापक अवसर उपलब्ध कराते हैं।

2017 से पहले यूपी में नहीं था विकास का इरादा : सीएम योगी ने सपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि निवेश और रोजगार के अवसर अब नोएडा और गाज़ियाबाद से आगे बढ़कर कुशीनगर और गोरखपुर जैसे जिलों तक फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य के युवाओं को नौकरी की तलाश में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने विकास पर ध्यान दिया होता, तो इस इलाके के युवाओं को रोजगार के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता।

सीएम योगी ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने दिलचस्पी दिखाई होती, तो कुशीनगर के युवाओं को



पलायन नहीं करना पड़ता। आज जब यूपी पुलिस में भर्ती होती है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई परीक्षा आयोजित करता है और मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटता हूँ, तो कुशीनगर के किसी युवा को नियुक्ति पत्र पाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पिछली सरकारों पर निशाना

और न ही विकास के काम हो पाए, सब कुछ ठप पड़ गया था। मुख्यमंत्री ने पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और कहा कि गरीबों के लिए बनी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के मौकों पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्ज़ा कर लिया था और गरीबों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए CM योगी ने कहा कि BJP की 'डबल-इंजन' सरकार आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करती और उसने पूरे राज्य में शांति बनाए रखी है।

जन्म से नहीं, माइग्रेशन से बढ़ी लखनऊ की आबादी, 15 साल में बढ़ी करीब 16 लाख जनसंख्या

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ का चेहरा अब केवल जन्म दर से नहीं, बल्कि माइग्रेशन से भी बदल रहा है। डेढ़ दशक में लखनऊ उन शहरों में शामिल हो गया है, जहां आबादी बढ़ाने में दूसरे जिलों और राज्यों से आकर बसने वाले लोगों की बड़ी भूमिका रही है। 2027 की जनगणना के लिए लखनऊ 61.99 लाख लोगों की हाउस करिया हुई है। वहीं, 2011 की जनगणना में जिले की आबादी 45.89 लाख थी। इससे करीब 16 लाख लोगों की बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल जन्म दर के आधार पर इतनी तेज वृद्धि संभव नहीं। राजधानी में रोजगार, उच्च शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, सरकारी

कार्यालय, आईटी और सेवा क्षेत्र के विस्तार ने लोगों को आकर्षित किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर लगातार घट रही है। ऐसे में लखनऊ जैसे बड़े शहरों की आबादी बढ़ने का प्रमुख कारण माइग्रेशन है।

हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा और पूर्वांचल के कई जिलों से लोग लखनऊ आए हैं। दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार और पढ़ाई के लिए यहां पहुंचे और स्थायी रूप से बस गए। राजधानी में आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण और सेवा क्षेत्र के विस्तार ने इस रफ्तार को और तेज किया है।

कैंसर-मधुमेह समेत 39 दवाएं सरस्ती : मरीजों को मिली बड़ी राहत, अधिक दाम वसूलने पर स्टोर मालिकों को होगी जेल ?

मुंबई, एजेंसी। देश के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आम जनता को सस्ती दवाएं मिलेंगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 39 नई दवाओं के दाम तय कर दिए हैं। अब पूरे देश में ये दवाएं एक ही कीमत पर मिलेंगी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इसकी सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी है। कोई भी कंपनी तय दाम से ज्यादा पैसे नहीं ले पाएगी।

इस नए आदेश से करोड़ों लोगों को फायदा होगा। सरकार ने आम और गंभीर दोनों बीमारियों की दवाओं के दाम घटाए हैं। इसमें ब्लड प्रेशर (बीपी) की दवाएं शामिल हैं। शुगर यानी मधुमेह की दवाएं भी सस्ती की गई हैं। इसके अलावा दिल की बीमारी,



इन्फेक्शन, मिर्गी और आंखों की दवाओं के रेट तय हुए हैं। दर्द, एचआईवी और कैंसर के इलाज की जीवनरक्षक दवाएं भी अब बेहद कम कीमत पर मिलेंगी।

मनमानी कीमत वसूलने पर सख्त एक्शन

सरकार ने कंपनियों को कड़ा संदेश दिया है। कोई भी मेडिकल स्टोर या

कंपनी इन दवाओं को तय रेट से महंगा नहीं बेच सकती है। अगर किसी ने भी मरीजों से ज्यादा पैसे वसूले, तो खेर नहीं होगी। सरकार उस दुकानदार या कंपनी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। ज्यादा वसूली हुई पूरी रकम ब्याज के साथ वापस ली जाएगी।

इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के कड़े नियमों का इस्तेमाल होगा। मुनाफाखोरी करने



करते थे। पैसों का असली सोर्स छिपाने के लिए पहले इस नकदी को रिश्तेदारों और जानकारों के बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता था। इसके बाद वही पैसा ट्रांसफर के जरिए आरोपियों के निजी खातों में पहुंचता था, ताकि इसे पूरी तरह से वैध कमाई दिखाया जा सके। इस गोरखधंदे का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के दोस्तों और रिश्तेदारों के करीब दो दर्जन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा, पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि चुराया

दुकान पर रेट लिस्ट लगाना बेहद जरूरी

नए नियमों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सभी दवा दुकानदारों और डीलरों को अपनी दुकान में नई रेट लिस्ट लगानी होगी। यह लिस्ट दुकान के सामने साफ अक्षरों में दिखनी चाहिए। इससे ग्राहक खुद दवाओं के सही दाम देख सकेंगे। एनपीपीए ने बताया है कि इन तय कीमतों पर जीएसटी अलग से लेगेगा। जो कंपनियां इन दवाओं को नए नाम से बाजार में ला रही हैं, उन्हें भी सरकार के इसी रेट नियम को मानना होगा।

वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

कौन सी दवा अब कितने में मिलेगी?

अधिसूचना के अनुसार, बीपी की एम्सोडिपिन, टेल्मिसार्टन और मेटोप्रोलोल सॉल्सिनेट कॉम्बिनेशन टैबलेट अब सिर्फ 12.03 रुपये में मिलेगी। इन्फेक्शन के इलाज की अर्माबिससिलिन और पोटैशियम क्लैवुलेनैट टैबलेट की कीमत अलग-

अलग फॉर्मूलेशन के हिसाब से 19.53 रुपये और 27.31 रुपये होगी। एचआईवी के इलाज की डारुनाविर, रिटोनाविर और डोल्यूटेग्राविर किट अब टेनेक्वेल्लेस 50 मिग्रा का इंजेक्शन अब 60,238.27 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा एरिफिरिन और मेटफॉर्मिन जैसी कई अन्य जरूरी दवाओं के अधिकतम रेट भी फिक्स कर दिए गए हैं।

समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरि



नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी बढ़ गई है। शनिवार (11 जुलाई) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को आधिकारिक तौर पर नौसेना के बेड़े में कमीशन कर दिया।नौसेना के साथ ही भारत के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है। यह प्रोजेक्ट 17ए के तहत बना छठा स्वदेशी युद्धपोत है और इसे नौसेना के इस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया है। बंदरगाह शहर स्थित नौसैनिक डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही वरिष्ठ नौसेना अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।इस मौके पर रक्षा मंत्री ने खुशी जाहिर की। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

उन्होंने इसे भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), भारतीय नौसेना, INS महेंद्रगिरि के चालक दल और देशवासियों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्रोंने कहा कि यह युद्धपोत भारत की बढ़ती रक्षा विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समुद्र में कई अभियानों को अंजाम देने में सक्षम

INS महेंद्रगिरि करीब 6,670 टन के कुल वजन और 28 नॉट (करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे) की अधिकतम गति वाला एक बहुउद्देशीय स्टील्थ युद्धपोत है, जो समुद्र में कई अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें उन्नत स्टील्थ विशेषताएं, हमलों को डेटलने और युद्ध में टिके रहने की बेहतरीन क्षमता, रडार पर कम दिखाई देने की विशेषता तथा उच्च स्तर की स्वचालित प्रणालियां शामिल हैं।

भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बूथ सशक्तीकरण और संगठन विस्तार पर जोर, आगामी अभियानों की बनी रणनीति

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में बूथ सशक्तीकरण, संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान, वृक्षारोपण अभियान, डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम और कारगरिल विजय दिवस सहित आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत बूथ संगठन है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्य करने वाला प्रत्येक



कार्यकर्ता चुनाव का वास्तविक योद्धा है और संगठन की सफलता का आधार भी वही है। उन्होंने पदाधिकारियों से बूथ स्तर तक नियमित प्रवास, संवाद और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने

विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की सही जानकारी दें तथा तथ्यों के आधार पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दें।उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती नियमित संपर्क, संवाद और कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संबंधों पर निर्भर करती है। सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित प्रवास करें, संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करें और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ संगठन के

सभी अभियानों को सफल बनाएगा।प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि भाजपा का पूरा संगठन बूथ आधारित है और सभी गतिविधियों का केंद्र बूथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बूथ जितना मजबूत होगा, संगठन उतना ही प्रभावी बनेगा। इसलिए प्रत्येक पदाधिकारी बूथ सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित संपर्क और प्रवास सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों, पुराने एवं नए कार्यकर्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जाए। संगठन का विस्तार केवल बैठकों से नहीं बल्कि सतत संपर्क और सक्रिय सहभागिता से संभव है।धर्मपाल सिंह ने आगामी वृक्षारोपण अभियान को

संगठन का महत्वपूर्ण जनअभियान बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज राष्ट्रीय आवश्यकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया जाना चाहिए।उन्होंने भाजपा के डिजिटल बूथ प्रशिक्षण अभियान को संगठन के तकनीकी सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। उनके अनुसार डिजिटल रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा सकेंगे।

विश्व जनसंख्या दिवस पर पूर्वोत्तर रेलवे में जागरूकता कार्यक्रम, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य पर किया गया जागरूक

लखनऊ। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा ऐशबाग स्थित रेलवे पोल्री वलीनिक में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद्र के निर्देशन में किया गया।कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय तिवारी, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. कुमार उमेश और डॉ. रुचिका किशोर ने उपस्थित रेल कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को बढ़ती जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा करते हुए परिवार नियोजन को स्वस्थ एवं समृद्ध समाज की आधारशिला बताया।चिकित्सकों ने कहा कि सीमित और सुनियोजित परिवार न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है, बल्कि बच्चों के बेहतर पालन-पोषण, शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने लोगों से परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों का उपयोग करने तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील की।कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संतुलित परिवार, स्वच्छ जीवनशैली और जनसंख्या स्थिरिकरण जैसे विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें परिवार कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में चिकित्सा कर्मियों, रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ समाज के निर्माण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा।

जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, चुनाव तक मौजूदा अध्यक्ष ही रहेंगे प्रशासक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए नई जिला पंचायतों के गठन तक वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। ये व्यवस्था नई जिला पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने शासनादेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि सामान्य जिला निर्वाचन-2021 के बाद गठित जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त

हो रहा है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक ही अस्तित्व में रहती है। इसी अधिनियम की धारा 21 के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी जिला पंचायत के कार्यकाल के साथ स्वतः समाप्त हो जाता है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 20 (3-क) के तहत यदि अपरिहार्य परिस्थितियों अथवा लोकहित में जिला पंचायत का चुनाव समय से कराना संभव न हो, तो राजा सरकार प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त कर सकती है। यह व्यवस्था अधिकतम छह माह तक प्रभावी रह सकती है और इस अवधि में जिला पंचायत की सभी शक्तियां, कर्तव्य एवं अधिकार प्रशासक अथवा प्रशासनिक समिति में निहित होंगे।

ग्रामीण युवाओं को गांव में ही मिलेगी आईएएस–पीसीएस की तैयारी, प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में बन रहें हार्डटेक डिजिटल लाइब्रेरी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में हार्डटेक डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जा रही हैं। इन पुस्तकालयों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), प्रांतीय सविल सेवा (पीसीएस) तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो सामग्री, डिजिटल वि्वज और लगभग 20 हजार डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को शहरों जैसी अध्ययन सुविधाएं गांवों में ही उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक और भौगोलिक बाधाएं उनकी सफलता के मार्ग में रुकावट न बनें।पंचायतीराज

विभाग के अनुसार पहले चरण में 32 जिलों की ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। प्रत्येक लाइब्रेरी को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, जहां विद्यार्थी पारंपरिक पुस्तकों के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से भी अध्ययन कर सकेंगे। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी होगी।सरकार ने प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी के विकास पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए हैं। इसमें लगभग दो लाख रुपये की लागत से प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य

अध्ययन से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1.30 लाख रुपये के सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण तथा करीब 70 हजार रुपये की लागत से आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। इन सुविधाओं से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पुस्तकालय और डिजिटल लर्निंग की सुविधा मिल सके।सरकार ने इन डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को सौंपी है। इनमें ई-बुक्स, वीडियो

लेक्चर, ऑडियो सामग्री, इंटरैक्टिव वि्वज और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ते हुए उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत बनाना है, जिससे वे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।धोजना के तहत अब तक 10,406 ग्राम पंचायतों की लाइब्रेरियों में पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जबकि 9,372 ग्राम पंचायतों में आधुनिक फर्नीचर की आपूर्ति भी पूरी हो चुकी है। विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी लाइब्रेरियों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पुस्तकालय और डिजिटल लर्निंग की सुविधा मिल सके।सरकार ने इन डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को सौंपी है।

ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया, प्रदेशभर से शुभकामनियां देने पहुंचे समर्थक और जनप्रतिनिधि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा का जन्मदिन शनिवार को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उत्साह और आत्मीयता के साथ मनाया गया। लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर सुबह से ही जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और बड़ी संख्या में नागरिकों का तांता लगा रहा। सभी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं तथा उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की।दिनभर उनके सरकारी आवास पर बधाई देने वाले का सिलसिला जारी रहा। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर लोगों ने जनसेवा, विकास कार्यों तथा उनकी सरल और संवेदनशील कार्यशैली की

दिल्ली के एआई आधारित स्लज मैनेजमेंट प्लांट का लखनऊ महापौर ने किया निरीक्षण

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ की महापौर सुष्मा खर्कवाल ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित दिल्ली जल बोर्ड के स्लज मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण कर वहां अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और स्लज प्रबंधन प्रणाली का विस्तृत अवलोकन किया। उनके साथ नगर निगम लखनऊ के कार्यकारीण उपाध्यक्ष एवं पापद दल के उपनेता सुशील तिवारी 'पम्मी' तथा नगर निगम के पर्षद भी मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्लांट में सैवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाले स्लज का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण कर उससे ईटों का निर्माण किया जा रहा है। इस तकनीक से एक ओर अपशिष्ट का सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल निस्सारण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उसे निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी संसाधन में बदला



जा रहा है।अधिकारियों के अनुसार यह प्लांट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पूरी तरह स्वचालित प्रणाली पर संचालित होता है। पहले एसटीपी से निकलने वाला स्लज सीधे यमुना नदी में पहुंच जाता था, जिससे प्रदूषण

की समस्या बढ़ती थी, लेकिन अब उसी स्लज का वैज्ञानिक उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है।महापौर सुष्मा खर्कवाल ने कहा कि इस प्रकार के नवाचार स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट



आधुनिक तकनीक से वन संरक्षण को नई दिशा

ऑटोमेटेड फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम एक उन्नत तकनीक है जो जंगलों में आग लगने की घटनाओं का तुरंत पता लगाकर संबंधित अधिकारियों को सूचित करती है। भारत में, भारतीय वन सर्वेक्षण और विभिन्न राज्य वन विभाग फोरेस्ट फायर अलर्ट एंड मानिटरिंग सिस्टम सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। जंगल की आग को ध्यान में रखते हुए स्फोरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम संस्करण 2.0२ लाया गया है और पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग कर रही है। इसी दिशा में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विकसित ऑटोमेटेड फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण सुनिश्चित कर रहा है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में विकसित यह तकनीक वन विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक तेज, प्रभावी और पारदर्शी बना रही है। इससे वन संपदा, वन्यजीवों और जैव विविधता की सुरक्षा को नई मजबूती मिली है।

अब कुछ ही मिनटों में मिलती है आग लगने की सूचना

पहले वनाग्नि की जानकारी प्राप्त करने और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में एक से दो घंटे का समय लग जाता था। इस दौरान आग कई बार बड़े क्षेत्र में फैल जाती थी। अब नई स्वचालित प्रणाली के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया केवल 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है। इससे समय रहते आग पर नियंत्रण संभव हो रहा है।

उपग्रह तकनीक से होती है सटीक निगरानी

यह प्रणाली अत्याधुनिक उपग्रह तकनीक पर आधारित है। उपग्रह जंगलों में तापमान में होने वाले असामान्य बदलाव की पहचान करता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद आग की पुष्टि होने पर संबंधित वन मंडल, रेंज और बीट स्तर के अधिकारियों को तत्काल एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से अलर्ट भेज दिया जाता है।

रियल टाइम मॉनिटरिंग से बढ़ी कार्यक्षमता

वन विभाग ने इस प्रणाली को जीआईएस आधारित रियल टाइम डैशबोर्ड से जोड़ा है। इसके माध्यम से अधिकारी वनाग्नि की घटनाओं पर लगातार निगरानी रखते हैं। सूचना मिलते ही फील्ड स्टाफ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई करता है और उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करता है। इससे भविष्य की रणनीति बनाने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता मिलती है।

जनजागरूकता और पूर्व तैयारी पर विशेष जोर

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग केवल तकनीक पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए जनभागीदारी को भी बढ़ावा दे रहा है। हर वर्ष वनाग्नि सीजन से पहले फायर लाइन निर्माण, जनजागरूकता अभियान, प्रशिक्षण तथा मौकें ड़िल आयोजित किए जाते हैं, ताकि आग की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से वन संपदा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनका मानना ​​है कि यह प्रणाली वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी मॉडल साबित होगी।

वन संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी पहल

छत्तीसगढ़ का ऑटोमेटेड फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम आधुनिक तकनीक, त्वरित सूचना प्रणाली और प्रभावी प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। इससे वनाग्नि पर समय रहते नियंत्रण संभव हो रहा है और राज्य की अमूल्य वन संपदा, वन्यजीवों तथा पर्यावरण की सुरक्षा को नई मजबूती मिल रही है। यह पहल विकसित छत्तीसगढ़ और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंडियाहैंडमेड: भारत की शिल्प विरासत के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म

इंडियाहैंडमेड का लोगो, जो संस्कृत शिल्प विरासत को दर्शाता है।

इंडियाहैंडमेड एक समर्पित डिजिटल मार्केटप्लेस है जो भारत की हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाता है। यह मंच कारीगरों और बुनकरों को सीधे खरीदारों से जोड़ता है, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करते हुए बाजार तक पहुंच का विस्तार करता है। यह जीआई-टैग और ओडीओपी वस्तुओं सहित विविध हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करता है, जिससे क्षेत्रीय शिल्प उत्पादों की विभिन्न स्थानों पर मौजूदगी बढ़ती है।

भारत दुनिया की सबसे समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं में से एक है। यह क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि समावेशी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। भारत में वर्तमान में अनुमानित 64.66 लाख हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर हैं। इस कार्यबल में महिलाओं की काफी भागीदारी है। अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार महिलाएं हथकरघा बुनकरों में 71 प्रतिशत और कुल कारीगरों का 64 प्रतिशत हैं। यह मजबूत भागीदारी विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में रोजगार और सशक्तिकरण का समर्थन करने में इस क्षेत्र की भूमिका को दर्शाती है।

बड़ी संख्या में कारीगरों और बुनकरों के बल पर यह क्षेत्र भारत के उभरते बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे-जैसे वाणिज्य तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, ऑनलाइन पहुंच इन शिल्प समुदायों को बाजार में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर रही है। डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से, पारंपरिक आजीविका तेजी से डिजिटल व्यापार के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर रही है। इंडियाहैंडमेड को 2023 में लॉन्च किया गया। यह इस विजन को एक समर्पित डिजिटल मार्केटप्लेस में बदल देता है। वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित, यह प्लेटफॉर्म हस्तनिर्मित उत्पादों की मौजूदगी को बढ़ाता है और विक्रेताओं के लिए बाजार के व्यापक अवसर के द्वार खोलता है। इंडियाहैंडमेड विक्रेताओं, खरीदारों और शिल्प विरासत का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई सुविधाओं के एक सेट के माध्यम से परंपराओं को ऑनलाइन बाजार में लाता है: विशेष ऑनलाइन मार्केटप्लेस: यह बुनकरों और कारीगरों को अपने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाता है।

खरीदारों की सीधी पहुंच: कारीगर और बुनकर सीधे खरीदारों से जुड़े हुए हैं, जिससे विचौलियों की

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो विभिन्न शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

ब्लॉग

मूल्य श्रृंखला का जुड़ाव: पीएम मित्र पार्क के जरिए कैसे भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र की बदल रही है तस्वीर

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो विभिन्न शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

सदियों से, भारत की पहचान उसके परिधानों से गहराई से जुड़ी रही है। चाहे वह कश्मीर के पश्मीना की लंबे समय तक रहने वाली गर्माहत हो, असम के मूंगा सिल्क की सुनहरी चमक हो, तमिलनाडु की शाही कॉजीवरम साड़ियाँ हों, चंदेरी की बुनाई हो या सूरत के कारीगरों की कपड़ों पर मशहूर कारीगरी। आज भी यह क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है, जो जीडीपी में 2.3त्न, औद्योगिक उत्पादन में 13त्न और निर्यात में 12त्न का योगदान देता है। खेती के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला यह क्षेत्र 45 मिलियन लोगों को सीधे तौर पर और 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। इससे ग्रामीण समुदायों को मजबूती मिलती है और देश भर में लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का रास्ता खुलता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के एक साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के उलट, भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग जगहों पर फैले हुए मॉडल के तौर पर विकसित हुई। कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, कपड़े सिलने और निर्यात जैसी गतिविधियाँ अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुईं, जिसका अर्थ था कि एक कपड़ा बनने के दौरान अक्सर कई राज्यों की सीमाओं से गुजरता था। इस बिखराव के कारण कई संरचनात्मक बाधाएँ पैदा हुईं। इसने बड़े पैमाने पर काम करने, आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन और आखिरकार मजदूरों को उत्पादकता को सीमित कर दिया।

इसके साथ ही, मल्टी-मॉडल संपर्क में कमियों की वजह से लॉजिस्टिक्स का बोझ भी बढ़ जाता है। प्रोडक्शन के अलग-अलग चरणों के बीच हर बार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या संचालने में अतिरिक्त खर्च और दुलाई का किराया लगता है। कई चरणों में लंबी दूरी तक सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने से कुल लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है और सामान को तेज़ी से बाजार तक पहुँचाने की क्षमता खत्म हो जाती है, जो आज की रिटेल व्यवस्था में बार-बार ऑर्डर देने वाले साइकल में एक बहुत बड़ी और नुकसानदायक कमी है।

वर्तमान में पर्यावरण से जुड़ी ज़रूरतों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 8त्न से 10त्न और औद्योगिक जल प्रदूषण में 20त्न है। हजारों छोटी-छोटी और अलग-अलग जगहों पर फैली इकाइयों में नियमों को लागू करना और सही तरीके से प्रबंधन करना पहले एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती रहा है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो विभिन्न शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

इन पाकों को कच्चे माल के मुख्य केंद्रों के पास रणनीतिक रूप से बनाने से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होत है और निर्माण के लिए बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इससे ज़रूरी बात यह है कि इस नज़दीकी से शुरुआत से आखिर तक ट्रैकिंग भी मुमकिन हो पाती है। चूँकि वैश्विक ब्रांड ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल प्रमाणिकरण की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये एकीकृत पार्क एक सत्यापन योग्य

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो विभिन्न शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो विभिन्न शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

खरीदार समर्थन प्रणाली के माध्यम से अधिक विश्वसनीय खरीदारी अनुभव से लाभ होता है। यह प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दस्तकारी उत्पादों की पेशकश करके विश्वास को भी मजबूत करता है। विक्रेताओं के लिए सरल ऑनबोर्डिंग: यह मंच कारीगरों, बुनकरों और उत्पादक संगठनों को बाजार तक पहुँचने के लिए एक निर्दिशत ऑनबोर्डिंग मार्ग प्रदान करता है। जीएसटी पंजीकरण के बिना विक्रेता एक नामांकन आईडी का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें केवल अपने राज्य के भीतर बेचने का आदेश है। यह पोर्टल को छोटे कारीगरों और पहली बार डिजिटल विक्रेताओं के लिए अधिक समावेशी और सुलभ बनाता है। इस प्लेटफॉर्म के पीछे कारीगर, बुनकर और उद्यम हैं जिनकी शिल्प परंपराएँ डिजिटल व्यापार के माध्यम से फल-फूल रही हैं।

सैटर्स हस्तनिर्मित शिल्प की गर्मी को रोजमर्रा की ज़िंदगी में लाता है। लकड़ी की सजावट और सुगंधित मोमबत्तियों से लेकर टेराकोटा दीये, संगमरमर की मूर्तियों और हथकरघा साड़ियों तक, प्रत्येक उत्पाद पर्याप्त निगरानी, परंपरा और सुंदरता की सोच को दर्शाता है। दस्तकार क्राफ्ट बेंट और बांस उत्पादों के माध्यम से 500 से अधिक कारीगरों के कौशल को आधुनिक घरों में ले जाता है। वे उच्च-गुणवत्ता, नियात-योग्य उत्पाद बनाते हैं, जो समकालीन घरों में सहजता से फिट होते हुए भारत की विरासत का जश्न मनाते हैं। विलेज क्राफ्ट हथकरघा परंपराओं की सादगी और ताकत का जश्न मनाता है। इसके सूती तैलिए, गमछा और बेडशीट कुशल कारीगरों द्वारा देखभाल के साथ बनाए जाते हैं, जो रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को आराम, गुणवत्ता और विरासत में निहित उत्पादों में बदल देते हैं। ये कहानियाँ हस्तनिर्मित उत्पादों को एक मानवीय चेहरा देती हैं, जो दिखाती हैं कि डिजिटल बाजार में परंपरा, कौशल और आजीविका एक साथ कैसे आती हैं। इंडियाहैंडमेड डिजिटल इंडिया की भावना को दर्शाता है, शिल्प को आजीविका के स्रोत और भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतिबिंब दोनों के रूप में मान्यता देता है। 60 लाख से अधिक कारीगरों को शामिल करने की योजना के साथ, यह मंच आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यह कारीगरों और बुनकरों को व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करता है और खरीदारों को विश्वास और आसानी से हस्तनिर्मित उत्पादों की खोज करने में मदद करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो विभिन्न शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो विभिन्न शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो विभिन्न शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

इंडियाहैंडमेड का एक स्क्रीनशॉट, जो कारीगरों और बुनकरों को प्रदर्शित करता है।

विश्व-स्तरीय पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे पर काम किया जा रहा है। ये विशेषताएँ स्थायित्व के उन मानकों को दर्शाती हैं, जिन्हें सभी सात पार्क साइटों पर स्थापित किया जा रहा है।

पूरे देश में एक साथ काम शुरू होने से सहकारी संघवाद की तेज़ी और सफलता दोनों साफ दिखती है, जहां सभी सात राज्यों के साथ समझौता जापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 100त्न ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी भी मिल गई है। पाँच ग्रीनफील्ड साइट्स के लिए जेवी एग्ज़ीमेंट और एसपीबी पूरी तरह से तैयार हैं, जिससे तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। 2,158 एकड़ में फैले सबसे बड़े पार्क, धार (मध्य प्रदेश) में 221,436.9 करोड़ के निवेश में दिलचस्पी दिखाई गई है। इसी तरह गुजरात (१13,084 करोड़), महाराष्ट्र (१12,925 करोड़), तमिलनाडु (१6,600 करोड़), उत्तर प्रदेश (१5,345.8 करोड़) और कर्नाटक (१1,700 करोड़) में भी काम को लेकर तेज़ी देखी गई है। तेज़ी से हो रहे इस काम के पीछे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह का सक्रिय नेतृत्व है। उनके कुशल नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय अपने कामकाज के तरीकों में तेज़ी लाया है, मंत्रालय ने प्रशासनिक रुकावटों को दूर किया है और राज्य सरकारों के साथ अभूतपूर्व स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है।

लेकिन आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असली पैमाना इसके मानवीय प्रभाव में दिखता है। प्रत्येक पार्क को संरचनात्मक रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यानी सभी सात स्थलों को मिलाकर, 21 लाख से अधिक औद्योगिक आजीविकाएँ, जो हमारे ग्रामीण परिवारों और महिलाओं को अहम सामाजिक-आर्थिक नींव प्रदान करती हैं, जो पारंपरिक रूप से परिधान निर्माण उद्योग की रीढ़ हैं।

यह व्यापक ढांचगत प्रयास वस्त्र क्षेत्र के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण 2030 के लिए एक अहम लॉन्चपैड का काम करता है, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक भारत के वस्त्र उद्योग को 350 बिलियन डॉलर की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। ऐतिहासिक विखंडन को विश्व स्तरीय, एकीकृत पैमाने से बदलकर करके, पीएम मित्र एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन ला रहा है। सशक्त नेतृत्व के मागदर्शन में, हम भारत को कव्रों के निर्विवाद, टिकाऊ और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी केंद्र के तौर पर स्थापित कर रहे हैं।

(लेखक **केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री हैं।व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।**)



ईरान और यूएई के प्रतिनिधियों में हुई झड़प मिसाल है कि बदली विश्व परिस्थितियों के बीच ब्रिक्स+ के सदस्य ना सिर्फ अलग धरातल पर खड़े हैं, बल्कि वे परस्पर विरोधी रुख भी खुलेआम अपना रहे हैं।

ब्रिक्स+ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नई दिल्ली में हुई बैठक एक बार फिर इस समूह के अंदर गहरा रहे मतभेदों को उजागर कर गई। बैठक के दौरान ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिनिधियों की बीच हुई झड़प मिसाल है कि बदली विश्व परिस्थितियों के बीच ब्रिक्स+ के सदस्य देश ना सिर्फ अलग धरातल पर खड़े हैं, बल्कि अब वे परस्पर विरोधी रुख भी खुलेआम अपना रहे हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यादिर निजामीपुर ने अपने देश पर अमेरिका और इजराइल के हुए हमले में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप यूएई पर लगाया। जबकि यूएई ने ईरान पर उसे अनुचित निशाना बनाने का इल्जाम मढ़ा। इससे ब्रिक्स+ में सर्व-सहमत दृष्टिकोण उभरने की संभावना और कम हो जाने के संकेत मिले हैं।

मेजबान भारत की सहानुभूति यूएई के साथ अधिक है, जिसके इजराइल और अमेरिका से बेहतर रिश्ते हैं। दूसरी तरफ चीन और ईरान के प्रतिनिधियों की द्विपक्षीय बैठक से साफ हुआ कि वे दोनों देश बदल रहे वैश्विक समीकरणों के बीच समान धरातल पर खड़े हैं। ऐसे में ब्रिक्स+ की बैठक का असल महत्त्व इस मौके पर हुई द्विपक्षीय वार्ताएं ही रही। इनमें एक खास मौका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और चीन के विदेश मंत्री (जो वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं) वांग यी की मुलाकात रहा। डोवाल और वांग सीमा विवाद पर अपने- अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि भी हैं।

दोनों ने भारत-चीन संबंध के ताजा हाल की समीक्षा की। इसी तरह की द्विपक्षीय वार्ताएं अन्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच भी हुई। इस रूप में नई दिल्ली में उनका जुटना सार्थक रहा। बहरहाल, जहां तक ब्रिक्स+ का प्रश्न है, तो उसके महत्त्व और भूमिका को लेकर भले जो कहा जाता हो, लेकिन असल में यह समूह दिशाहीनता का शिकार होता नजर आ रहा है। इसी बात के संकेत पिछले महीने ब्रिक्स+ विदेश मंत्रियों की बैठक में भी मिले थे। सितंबर के मध्य में जब ब्रिक्स+ शिखर सम्मेलन होगा, तो उसमें कोई अलग नजारा होगा या इन देशों के सर्वोच्च नेता नजरिए में फर्क को पाट पाएंगे, इसकी संभावना भी कम ही है।

प्रबंधन और आध्यात्म का मर्म समझने वाला होगा राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ, महासचिव लेंगे अंतिम निर्णय

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी का मुद्दा इन दिनों सुर्विषयों में बना हुआ है। मामले की जांच के दौरान कई बड़ी खामियां सामने आई हैं। इस बीच मंदिर के प्रशासनिक और प्रबंधकीय व्यवस्था सभालने वाले CEO की नियुक्ति प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि CEO नियुक्त करने वाली 3 सदस्यीय समिति 2-3 दिन में बैठक करेगी।

जानकारी के मुताबिक CEOनियुक्त करने वाली समिति में रियायर्ड जज प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (रियायर्ड) विष्णुकान्त चतुर्वेदी और न्यूक्लियर साईंटिस्ट सुरेश हावरे शामिल हैं। ये सभी बैठक करेंगे और इस मामले पर चर्चा करेंगे।



महासचिव लेंगे अंतिम निर्णय

न्यूक्लियर साईंटिस्ट सुरेश काशीनाथ हावरे ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए बताया कि श्री राम मंदिर केCEO का नाम तय करना मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि

निर्भर करेगा कि इंटरव्यू देने कितने लोग आते हैं और उनमें प्रबंधन और आध्यात्म की कितनी समझ है। साथ ही मंदिर और धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है और मंदिर सभालने का कोई अनुभव भी है? उन्होंने कहा कि इन तमाम बातों पर ही ये निर्भर होगा कि मंदिर ट्रस्ट को योग्य उम्मीदवारों के पैनल में कितने नाम भेजे जाएं।

सुरेश हावरे ने बताया कि समिति की होने जा रही बैठक में तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। CEO की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का आवेदन कैसे और कब मांगा जाए?

तीन चरण के बाद फाइनल पैनल में कितने लोगों के नाम मंदिर ट्रस्ट को भेजे जाएं?

नियुक्त होने वाले CEO का वेतन और अन्य सुविधाएं क्या होंगी?

समिति सिर्फ योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तय करके मंदिर ट्रस्ट को सौंप देगी।

क्या होनी चाहिए विशेषता

उन्होंने बताया कि पैनल में अंतिम रूप से चयन उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी ये इस बात पर

मेरठ छात्रा हत्याकांड : पीड़ित परिवार से मिले पूर्व विधायक संगीत सोम, आर्थिक मदद का एलान, न्याय का दिलाया भरोसा



आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ में छात्रा हत्याकांड को लेकर जारी सियासी गतिविधियों के बीच शनिवार को पूर्व विधायक संगीत सोम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि बेटी को हर हाल में न्याय मिलेगा। साथ ही

वकील की फीस के लिए आर्थिक सहायता देने का भी एलान किया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान संगीत सोम ने कहा कि मृतक छात्रा पूरे समाज की बेटी थी और उसके साथ जो हुआ, वह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ गलत हुआ है, इसलिए उसे न्याय

पत्नी की विदाई को लेकर युवक टावर पर चढ़ा

जौनपुर। जफराबाद थाना के नेवादा गांव में शुक्रवार रात पत्नी की विदाई न होने से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब तीन घंटे तक चले झुमे के बाद पुलिस ने पत्नी और उसके परिजनों को मौके पर बुलाकर समझाइश दी, जिसके बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया।शहर कोतवाली क्षेत्र के चाचकपुर फूलमंडी मोहल्ला निवासी गुलशन मौर्य का कुछ दिन पहले पत्नी साधना मौर्य से विवाद हो गया था। इसके बाद साधना अपने मायके सैदनपुर चली गई थी। शुक्रवार को गुलशन पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा, लेकिन परिजनों ने विदाई से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर वह सीधे नेवादा गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया।घटना की सूचना मिलते ही जफराबाद थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता, शहर कोतवाल अनीता सिंह, लाइनजागर थाना प्रभारी केके सिंह और जलालपुर थानाध्यक्ष सतेंद्र विक्रम सिंह भी मौके पर पहुंचे।

विद्यालय अनुशासन का मंदिर : कृपाशंकर सिंह



विद्यालय की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण कर जीवन की दिशा और संस्कार प्राप्त किए। श्री सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता की पहली नींव उसके विद्यालय में ही रखी जाती है।

विद्यालय केवल शिक्षा केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन, नैतिकता और व्यक्तित्व निर्माण का मंदिर होता है। उन्होंने कहा कि आज वे जिस भी स्थान पर हैं, उसमें तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज के शिक्षकों के मार्गदर्शन, अनुशासन और शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्व सांसद विद्यासागर सोनकर, पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ज्ञानप्रकाश सिंह,सुरेंद्र सिंह,समेत आदि लोगों ने सम्बोधित किया।

पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार के घर में घुसा सांप, बारिश से जलभराव बना मुसीबत, नगर आयुक्त से की शिकायत



आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ।मेरठ में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश ने मेरठ के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा कर दी है। रोहटा रोड स्थित ऐरा कॉलोनी की पानी में डूबी हुई है। हालात ऐसे हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार के घर में भी सांप घुस गया। इसके बाद उन्होंने नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से फोन पर बात कर जल

निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार रोहटा रोड स्थित ऐरा कॉलोनी के मकान संख्या ए-18-19 में रहते हैं। उन्होंने बताया कि लगातार बारिश के कारण कॉलोनी में पिछले दो दिनों से जलभराव बना हुआ है। गंदा पानी घरों तक पहुंच गया है और पानी की निकासी नहीं होने से झाड़ियों में रहने

प्रवीण कुमार ने बताया कि जलभराव के कारण क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी हो रही है। उन्होंने नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से फोन पर शिकायत कर जल्द पानी निकासी और आवश्यक व्यवस्था कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द जलभराव दूर नहीं हुआ तो बीमारी फैलने के साथ-साथ जहरीले जीवों का खतरा भी बढ़ सकता है।



वारदात को जिस बेरहमी से अंजाम दिया गया, उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। जयराम ने रास्ते में चालाकी करते हुए 10 साल के मासूम अंकुश को एक पेटोल पंप पर ही छोड़ दिया और सीमा को बहला-फुसलाकर एक सुनसान खेत की तरफ ले गया। वहां पति जसराम पहले से ही हथियार लेकर घात लगाए बैठा था। खेत में पहुंचते ही पति ने सीमा के पैर जकड़ लिए और देवर जयराम ने चालाकी दिखाई और सीमा व उसके बेटे अंकुश को अगवानपुर से अपनी बाइक पर बैठाकर मौढ़ा तैय्या की तरफ चल दिया।

बाद जयराम वापस पेट्रोल पंप पहुंचा। वहां मासूम अंकुश रोते हुए अपनी मां के बारे में पूछने लगा। जयराम को डर सताने लगा कि अगर बच्चा घर जाकर सच बता देगा तो उनका राज खुल जाएगा। इसी खौफ के कारण उसने अपनी ही गोट में खेले मासूम भतीजे अंकुश की भी गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर दी।

पुलिस को उलझाने के लिए सीमा विवाद का बुना ताना-बाना

इस दोहरे कत्ल को अंजाम देने के बाद दोनों शांतिर भाइयों ने कानून की आंखों में धूल झांकने के लिए एक सोची-समझी योजना बनाई थी। उन्होंने मृतका और बच्चे के शवों को गांव के सुदूर खेतों में ले जाकर फेंका। यह इलाका अमरौहा जिले की सीमा के करीब आता है। अनपढ़ होने के

उत्तर प्रदेश

कार्य क्षेत्र और दायित्व

इसके साथ ही CEO का कार्य क्षेत्र और दायित्व क्या होगा ये भी अहम बात है। फिलहाल ये तय है कि नियुक्त CEO मंदिर ट्रस्ट के महासचिव को रिपोर्ट करेगा और नियुक्त CEO को अयोध्या में ही रहना होगा।CEO को वेतन, रहने के लिए मकान और गाड़ी भी मिलेगी।

सुरेश हावरे ने बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगी। इंटरव्यू के लिए आवेदन रियायर्ड और वर्किंग कोई भी कर सकता है। बस उनको धर्म और प्रबंधन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी समिति में शामिल हम तीनों लोगों की बैठक नहीं हुई है हम जल्दी बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।आवेदन कैसे लेना है यह भी

बैठक में तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए कुछ योग्यता भी बैठक में तय की जा सकती हैं। लेकिन जो भी नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण योग्यता धर्म और आध्यात्म के प्रति कितनी रचि रखते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही प्रशासन, प्रबंधन और वित्तीय अनुभव का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि CEO का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मंदिर की प्रबंधकीय, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था देखने की होगी।

महासचिव को सौंपी जाएगी सूची

उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में आवेदन आने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उन नाम पर विचार करके महासचिव को सूची

सौंप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चाहे वो कार्यवाहक महासचिव हो या फिर पूर्णकालिक महासचिव हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी महासचिव का दायित्व निभा रहा होगा उसकी सूची दी जाएगी।

कौन हैं सुरेश हावरे

सुरेश हावरे मंदिर ट्रस्ट के CEO के चयन के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति के सदस्य हैं। वो एक सेवानिवृत्त परमाणु वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में 27 साल बिताए हैं। हावरे शिरडी में श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट के प्रमुख भी रह चुके हैं, इसके साथ ही वो वर्तमान में रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के अध्यक्ष और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मेंबर भी हैं। उन्होंने ‘टेम्पल मैनेजमेंट’ नामक पुस्तक भी लिखी है।

12 सालों से टण्डा पड़ा है इलेक्ट्रिक शवदाह गृह

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। रामघाट पर बना इलेक्ट्रिक शवदाह गृह पिछले 12 सालों से निष्क्रिय पड़ा है। गोमती नदी के किनारे स्थित वर्ष 2014 में तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित इस शवदाह गृह में आज तक एक भी चिता नहीं जली है। वर्तमान में इसका उपयोग कफन और अन्य सामग्री रखने के लिए किया जा रहा है, और इसके सिस्टम में जंग लग गई है। रामघाट पर प्रतिदिन लगभग 40 शवों का अंतिम संस्कार होता है। जौनपुर और आजमगढ़ जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से भी लोग अंतिम संस्कार के लिए यहां आते हैं।आधुनिक सुविधा होने के बावजूद, लोगों को लकड़ी खरीदकर पारंपरिक चिता सजानी पड़ती है। घाट पर चिमनी वाले आधुनिक शवदाह गृह का शिलापटु देखकर लोग अक्सर इसकी

निष्क्रियता पर सवाल उठाते हैं।

बताया गया कि कि वर्ष 2014 में दो चिमनी वाले शवदाह गृह बनाए गए थे।इनका मुख्य उद्देश्य कम लकड़ी का उपयोग कर शवों का अंतिम संस्कार करना थाय जहां सामान्य चिता में लगभग दो क्विंटल लकड़ी लगती है, वहीं इसमें एक क्विंटल लकड़ी में शवदाह का दावा किया गया था। हालांकि, चिमनी वाले शवदाह गृह में लकड़ी ठीक से न जल पाने के कारण यह व्यवस्था कभी शुरू नहीं हो पाई। उस समय जांच की बात कही गई थी, लेकिन उसका परिणाम आज तक सामने नहीं आया। घाट के डोंमराजा राम मूरत चौधरी और सूरज चौहान ने पुष्टि की कि मशीन लगने के बाद से यह एक दिन भी नहीं चली है। उन्होंने जिम्मेदारी पर इस महत्वपूर्ण स्थल की उपेक्षा का आरोप लगाया।

44 साल का विश्वनाथ मंदिर न्यास, 12 साल स्थायी अध्यक्ष के बिना रहा, अब तक 5 को तैनाती मिल सकी



आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। 44 साल पुराने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अब तक करीब 12 साल बिना स्थायी अध्यक्ष के काम किया है। काशी नरेश डॉ. विभूति नारायण सिंह से प्रो. नागेंद्र पांडेय तक कुल पांच स्थायी अध्यक्ष ही रहे हैं। 18 महीने से ज्यादा समय में न्यास अध्यक्ष का पद खाली है। राज्य सरकार की ओर से नामित पांच सदस्यों के नाम भी घोषित नहीं किए गए। 1983 से 2026 के बीच चार बार अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हुई

है।

मंदिर प्रशासन ने दिसंबर 2024 में न्यास परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से एक महीने पहले ही संभावित अध्यक्ष और पांच नामित सदस्यों के नाम शासन को भेज दिए थे। 18 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है फिर भी न्यास परिषद का गठन नहीं किया गया। वर्तमान में केवल चार पदेन सदस्य ही काम कर रहे हैं। इनमें तीन अधिकारी शामिल हैं। 1983 से अब तक ऐसी स्थिति चार बार बनी, जब न्यास अध्यक्ष और

न्यास परिषद का होना जरूरी है। अध्यक्ष और सदस्यों की मौजूदगी में बैठक में सहमति बनती है। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम–1983 के नियमों के पालन के लिए यह आवश्यक भी है। जब से अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब से दर्शन करने भी नहीं गया हूं। – प्रो. नागेंद्र पांडेय, पूर्व अध्यक्ष, न्यास परिषद श्रीकाशी विश्वनाथ न्यास का कार्यकाल समाप्त होने से एक महीने पहले ही संभावित सदस्यों के नाम शासन को भेज दिए गए थे। मंदिर से जुड़े सभी कार्य नियमित रूप से होते रहे हैं। इस संबंध में समय–समय पर पत्राचार भी हुआ है। अब शासन से निर्णय का इंतजार है। – विश्वकृष्ण मिश्रा, सीईओ, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर

नामित सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो रही है। 1983 से 2002 तक मंदिर न्यास के अध्यक्ष काशी नरेश डॉ. विभूति नारायण सिंह थे। उनके निधन के बाद 2002 में मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारी टीपी तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया था।

उन्होंने कुछ ही महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2009 तक यह पद खाली रहा और मंडलायुक्त कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाते रहे। छह साल बाद 2009 में प्रदेश सरकार ने पंडित

हरिहर कृपालु त्रिपाठी को तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष नामित किया। 2012 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद करीब डेढ़ साल तक यह पद खाली रहा। वर्ष 2013 में पं. अशोक द्विवेदी को न्यास का अध्यक्ष बनाया गया। वह 2003 में न्यास के सदस्य भी रह चुके थे। वर्ष 2016 में उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। 2019 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2021 में प्रो. नागेंद्र पांडेय को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

हादसे में किशोर की मौत, दोघायल

जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र के मुसईपुर गांव में बीते शुक्रवार की रात करीब 12 बजे एक खड़े डीसीएस से भिड़ने के बाद तेज रफ्तार ट्रेलर घर में घुस गया। इस हादसे में किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी तरफ एक किशोर और महिला घायल हो गये हैं।वताते है कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी डीसीएस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डीसीएस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक मकान में घुस गई। हादसे में मकान के बाहर से रहे 17 वर्षीय किशोर सूरज गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई 15 वर्षीय भाई राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी ओर चारपाई पर सो रही मंजू देवी, पत्नी रामजियावन गुप्ता भी घायल हो गईं। और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।



